[2012] 8 एस. सी. आर. 813]

टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्प. लिमिटेड एव अन्य।

बनाम

जय प्रकाश एसो॰ लिमिटेड।

(सिविल अपील संख्या 3682/2007)

सितंबर 25,2012

[आर. एम. लोधा, एनिल आर. डेव और रंजन गोगोई, जे. जे.]

मध्यस्थता-पोषणीयता-निष्पादन के लिए अनुबंध कार्यों में मध्यस्थता एक खंड था-शिकायत उत्तरदाता-ठेकेदार कि हालांकि काम किया गया था पूरा हो गया, अंतिम बिल तैयार नहीं किया गया था-मध्यस्थता कार्यवाही शुरू की गई, जिसके दौरान अंतिम विधेयक तैयार किया गया और अपीलार्थी द्वारा मध्यस्थों के समक्ष रखा गया-निगम - इसके बाद, मध्यस्थता की एक और प्रक्रिया शुरू की गई प्रत्यर्थी-ठेकेदार के विशिष्ट दावे-की रखरखाव क्षमता मध्यस्थता कार्यवाही का दूसरा दौर-अभिनिर्धारित ;- . प्रत्यर्थी की पात्रता-ठेकेदार विषय नहीं था मध्यस्थों के समक्ष पूर्व कार्यवाही का मामला - प्रतिवादी-ठेकेदार का दावा अंतिम बिल तैयार होने और मध्यस्थों के सामने रखे जाने के बाद स्पष्ट हो गया-ये हैं विशिष्ट दावे, परिमाणीकरण के बाद, जिन्हें संदर्भित किया गया था पश्चातवर्ती मध्यस्थता कार्यवाहियों में मध्यस्थ-इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि के संबंध में मध्यस्थता कार्यवाही प्रत्यर्थी के विशिष्ट दावे-ठेकेदार में वर्जित था पक्षकारों के बीच पूर्ववर्ती मध्यस्थता कार्यवाही का दृष्टिकोण।

मध्यस्थता-मध्यस्थता पुरस्कार-चुनौती-मध्यस्थता की शक्ति न्यायालय-कार्यों के निष्पादन के लिए अनुबंध-उत्पन्न होने वाले विवाद वहाँ से-मामले के संदर्भ में मध्यस्थता के लिए संदर्भित के अनुबंध दावे में निहित मध्यस्थता खंड प्रत्यर्थी-प्रतिभूति जमा की वापसी के लिएठेकेदार पर मध्यस्थों द्वारा इस आधार पर निर्णय नहीं लिया गया कि यह था मध्यस्थता योग्य नहीं-आयोजितः ऐसी स्थिति में, यह स्पष्ट रूप से परे था दावा करने के लिए निचली अदालत की शक्ति अदालत ने दावे को दरकिनार कर दिया, हालांकि, यह गलत एक मध्यस्थ द्वारा दावे के निर्णय को निर्देशित करने में इसके द्वारा नामित-इस मुद्दे को इसके लिए छोड़ दिया जाना चाहिए था सहमत प्रक्रिया के अनुसार निर्धारण दलों द्वारा मध्यस्थता-मध्यस्थता अवार्ड -- ब्याज का अनुदान-औचित्य-आयोजितः एक्सप्रेस को देखते हुए

उचित नहीं है पक्षों के बीच अनुबंध में निहित बार। मध्यस्थता-मध्यस्थता पुरस्कार-पद के लिए ब्याज का अनुदान पुरस्कार अवधि-औचित्य-अभिनिर्धारित- न्यायसंगत है।

अपीलार्थी और प्रत्यर्थी-ठेकेदार ने कुछ कार्यों के निष्पादन के लिए एक अनुबंध में प्रवेश किया टिहरी पनबिजली परियोजना से जुड़ाव। हालांकि विचाराधीन कार्य पूरे हो गए थे, अंतिम बिल प्रतिवादी-ठेकेदार तैयार नहीं था और सुरक्षा बैंक गारंटी के माध्यम से प्रस्तुत धन नहीं था रिहा कर दिया। पक्षकार सभ ओहि अनुसार मध्यस्थताक लेल गेलथि। अनुबंध/समझौते के तहत मध्यस्थता खंड के साथ। मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान, अपीलार्थी निगम ने अंतिम विधेयक प्रस्तुत किया।

इसके बाद, एक और मध्यस्थता कार्यवाही विशिष्ट दावों के लिए पक्षों के बीच शुरू किया गया प्रत्यर्थी-ठेकेदार। मध्यस्थता पुरस्कार में पारित किया गया उपरोक्त मध्यस्थता कार्यवाही ने प्रतिवादी को अभिनिर्धारित किया रुपये का हकदार ठेकेदार। 10.17 लाख के कारण 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ किया गया कार्य पुरस्कार की तारीख तक दावे का आह्वान और @ 12 % पी. ए. पुरस्कार की तारीख से भुगतान तक या भुगतान तक पुरस्कार को न्यायालय का नियम बना दिया गया था, जो भी पहले हो। जहाँ तक प्रत्यर्थी के दावे का संबंध है-रुपये का ठेकेदार। 12.50 अपीलार्थी के पास जमा में पड़े लाखों-निगम, मध्यस्थों ने इसे इसके दायरे से बाहर माना मध्यस्थता कार्यवाही में उठाया गया विवा पुरस्कार के विशिष्ट भागों के खिलाफ आपत्तियाँ जिसे संबंधित पक्षों ने व्यथित महसूस किया था, दायर किया गया था जिला न्यायाधीश के समक्ष। जिला न्यायाधीश (ट्रायल कोर्ट) प्रत्यर्थी-ठेकेदार को दोनों का हकदार ठहराया राशि-रु। 10.17 लाख भी रु। 12.50 लाख और इसके बाद दोनों राशियों के संबंध में एक आदेश पारित किया गया 12 प्रतिशत लटकन लाइट की दर से उस पर ब्याज के साथ और पद पुरस्कार अवधि के लिए 6 प्रतिशत। अपील में, उच्च अदालत ने रुपये का पुरस्कार बरकरार रखा। 10.17 लाख, हालांकि, रुपये के दावे के संबंध में। 12.50 लाख, यह देखा गया कि उक्त राशि द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती थी निचली अदालत के रूप में उक्त हक में नहीं गया था मध्यस्थों, और इस तरह के दावे को निपटाने के लिए रिमांड किया उसके द्वारा नियुक्त मध्यस्थ। उच्च न्यायालय ने सौदा नहीं किया ब्याज के सवाल के साथ। तत्काल अपील में, अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि प्रतिवादी-ठेकेदार ने एक और प्रक्रिया का सहारा लिया प्रथम में ऐसी अनुमति मांगे बिना मध्यस्थता मध्यस्थता कार्यवाही; और इस प्रकार मध्यस्थता विवादित पुरस्कार की ओर ले जाने वाली कार्यवाही बिना किसी कानून के अधिकार के थी। रुपये के दावे के संबंध में। 12.50 लाख, अपीलार्थियों ने तर्क दिया कि उक्त दावा था मध्यस्थों द्वारा निर्णय नहीं लिया गया और इस तरह के एक स्थिति यह

विचारण न्यायालय की शक्ति से परे थी प्रत्यर्थी-ठेकेदार के पक्ष में उक्त दावा; कि हालांकि उच्च न्यायालय को अलग रखने में उचित ठहराया गया था रु. का दावा। 12.50 लाख, यह निर्देशित नहीं कर सकता था नामित मध्यस्थ द्वारा उक्त मुद्दे का निर्णय इसके द्वारा। इसके अलावा, अपीलकर्ताओं ने खंड 1.2.14 पर भरोसा किया और 1.2.15 अनुबंध के भाग II का यह तर्क देना कि इसके तहत ब्याज देने के लिए एक विशिष्ट प्रतिबंध था और इस प्रकार प्रत्यर्थी-ठेकेदार के पक्ष में ब्याज का पुरस्कार पूरी तरह से असमर्थनीय था।

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया;--

निर्धारण ;-- 1.1 . प्रत्यर्थी की पात्रता दो राशियों के लिए ठेकेदार-Rs.10,17,461/- और रु. 12.50 लाख पहले की विषय वस्तु नहीं थी। मध्यस्थों के समक्ष कार्यवाही जो उत्पन्न हुई प्रत्यर्थी की शिकायत-ठेकेदार कि हालांकि कार्य का निष्पादन पूरा हो गया था, अंतिम बिलतैयार नहीं किया गया था और आगे कि कुछ राशियाँ प्रतिभूति के रूप में जमा में पड़ा हुआ पैसा वापस नहीं किया गया था। एक बार अंतिम बिल तैयार किया गया और उसके सामने रखा गया मध्यस्थों ने प्रत्यर्थी का दावा किया-ठेकेदार को मिला क्रिस्टलीकृत। परिमाणीकरण के बाद ये विशिष्ट दावे हैं, जिसे कार्यवाही में मध्यस्थों को भेजा गया था जिसमें पुरस्कार पारित किया गया है। इसलिए ऐसा नहीं होगा। पूर्ववर्ती मध्यस्थता कार्यवाही को देखते हुए वर्जित दलों के बीच। इसके अलावा, द्वारा पारित एक आदेश से 15 जनवरी, 1994 को मध्यस्थों को ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त आदेश में मध्यस्थों ने स्पष्ट रूप से दर्ज किया था कि

"। . . . दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि हमें निर्णय लेना चाहिए रुपये की जमा राशि की वापसी से संबंधित दोनों विवाद। 12. 5 लाख और रुपये के अंतिम बिल का भुगतान। 10.00 लाख और अजीब। . . . " इन परिस्थितियों में, पुरस्कार जहाँ तक Rs.10 का दावा है, 17,461/-

मध्यस्थ और निचली अदालतों द्वारा पुष्टि नहीं की गई है इस न्यायालय द्वारा किसी भी और जांच की आवश्यकता है। [पैरा 9] [824 सी-एच]

1.2 . जहाँ तक राशि के संबंध में दावा है रु. 12.50 लाख का संबंध है, प्रतिवादी की पात्रता-उक्त राशि के लिए मध्यस्थों द्वारा इस आधार पर निर्णय नहीं दिया गया कि उक्त मुद्दा एक मध्यस्थ मुद्दा नहीं था और इसका समाधान या तो एक सौहार्दपूर्ण प्रक्रिया द्वारा या द्वारा किया जाना चाहिए

या , वसूली के लिए एक सूट दायर करके। यदि उपरोक्त दावा पर मध्यस्थों द्वारा निर्णय नहीं दिया गया था तो ट्रायल कोर्ट (जिला न्यायाधीश) उक्त दावे का आदेश देने में स्पष्ट रूप से गलत थे। इसलिए, उच्च न्यायालय पूरी तरह से सही थी , डिक्री के उक्त भाग को उलटना। हालांकि, वहाँ है उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के लिए कोई उचित आधार नहीं है कि प्रत्यर्थी का हक-ठेकेदार को उक्त राशि अब मध्यस्थ द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए उसके द्वारा नामित किया गया। बल्कि, उपरोक्त मुद्दे को होना चाहिए था के अनुसार निर्धारण के लिए छोड़ दिया गया बिल्कुल भी, निर्णय के एक और दौर में जाने के लिए इच्छुक इस स्तर पर। उच्च के क्रम का उपरोक्त भाग इसलिए, न्यायालय हस्तक्षेप करता है और इसके अधीन है इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ, पक्षकार हैं उनके उपचारों पर काम करने की अनुमति दी जा सकती है मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में सबसे अच्छा और सबसे उपयुक्त माना जाता है। [पैरा 10] [825-ए-ई]

2.1 . पक्षों के बीच समझौते अनुबंध के खंड 1.2.14 और 1.2.15 से स्पष्ट रूप से पता चलतहै कि इसके बावजूद द्वारा विचार की गई परिस्थितियों का कुछ अतिव्यापी दो खंडों में, ठेकेदार को कोई ब्याज देय नहीं है कार्यों के लिए अंतरिम या अंतिम भुगतान में देरी के लिए गारंटी के रूप में जमा की गई या जमा की गई किसी भी राशि पर। उपर्युक्त सुविचारित परिणाम दोनों ऐसी स्थिति में लागू होंगे जहाँ भुगतान को रोकना पक्षों के बीच किसी विवाद या मतभेद के कारण या अन्यथा भी होता है। चूंकि उक्त खंड 1.2.14 और 1.2.15 ने एक स्पष्ट प्रावधान लागू किया है। मनोरंजन या ब्याज के भुगतान पर रोक भुगतान न करने या भुगतान में देरी की स्थिति प्रतिभूति जमा में किए गए या पड़े हुए कार्य के लिए देय राशि, के दावे पर विचाराधीन लघु ब्याज का अनुदान Rs.10,17,461/- उचित नहीं है। पुरस्कार और साथ ही निम्नलिखित न्यायालयों के आदेशों को तदनुसार संशोधित किया गया है - उपरोक्त सीमा। [पारस 11,12 और 17] [825-एफ; 826-ई एफ; 829-जी-एच-; 830-ए-बी]

2.2 . तथापि, पद-पुरस्कार के लिए ब्याज का अनुदान अवधि कुछ अलग आधार पर खड़ी होगी। 17,461/- की राशि पर ब्याज का अनुदान आदेश की तारीख या अवार्ड की तारीख तक भुगतान, जो भी पहले हो, बरकरार रखा जाता है। तथ्यों मे मामले में, ब्याज की दर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष होनी चाहिए। के बीच मध्यस्थता कार्यवाही में निर्धारित के रूप मे पार्टियाँ। [पैरा 18] [830-बी-डी-ई]

सचिव, सिंचाई विभाग, उड़ीसा सरकार और अन्य बनाम जी. सी. रॉय और अन्य . (1992) 1 एससीसी 508: 1991 (3) पूरक। एस. सी. आर. 417; कार्यकारी अभियंता, ढेंकलाल माइनर (मृतक)

आईआरएस द्वारा। और अन्य (2001) 2 एस. सी. सी. 721: 2001 (1)एससीआर 264; यूनियन ऑफ इंडिया बनाम क्राफ्टर्स इंजीनियर्स एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड (2011) 7 एससीसी 279: 2011 (8) एससीआर 196; सईद अहमद एंड कंपनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। (2009) पालघाट और अन्य (2010) 8 एस. सी. सी. 767: 2010 (10) एससीआर 487 और उड़ीसा राज्य बनाम। बी. एन. अग्रवाल (1997) 2 एस. सी. सी. 469: 1997 (1) एससीआर 704-पर निर्भर। पोर्ट ऑफ कलकत्ता बनाम न्यासी मंडल। इंजीनियरों डी-स्पेस-एज (1996) 1 एस. सी. सी. 516: 1995 (6) पूरक। एससीआर 327 ; मदनानी कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य (2010) 1 एस. सी. सी. 549: 2009 (16) एससीआर 216 ; एशियन टेक लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य 2009 10 एससीसी 354: 2009 (14) एस. सी. आर. 182 और कार्यकारी सहायक (सिंचाई), बालीमेला और अन्य बनाम अभदूत जेना और अन्य (1988) 1 एससीसी 418: 1988 (1) एस. सी. आर. 253-संदर्भित। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम अमृतसर गैस सेवा और अन्य (1991) 1 एस. सी. सी. 533: 1990 (3) पूरक। एस. सी. आर. 196-उद्धृत।

मामला कानून संदर्भः

1990 (3) पूरक। एस. सी. आर. 196 उद्धृत	उस पर भरोसा करें	पैरा 7
1997 (1) एससीआर 704	संदर्भित किया गया है	पैरा 7
2009 (14) एस. सी. आर. 182	संदर्भित किया गया है	पैरा 7
1991 (3) पूरक। एस. सी. आर. 417	पर निर्भर	पैरा 13
2001 (1) एससीआर 264	भरोसा किया गया	पैरा 13
2011 (8) एससीआर 196	उस पर भरोसा करे	पैरा 13
1995 (6) पूरक। एस. सी. आर. 327	को संदर्भित किया गया	पैरा 14
2009 (16) एससीआर 216	को संदर्भित किया गया	पैरा 14

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं—3682/ 2007

[उत्तरांचल (नैनीताल) उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 20.07.2006

अपील संख्या 879/2001 में पारित से उतपन।]

पुनीत तनेजा, गुरप्रीत एस. परवांडा, मोनिका त्यागी, शैल कुमार द्विवेदी।—अपीलर्थियों के लिए 1

एस. बी. उपाध्याय, पवन उपाध्याय, पवन किशोर शर्मिला उपाध्याय।—प्रतिवादी के लिए

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था--

रंजन गोगोई, जे. 1. यह अपील इसके खिलाफ निर्देशित ह नैनीताल में उत्तरांचल उच्च न्यायालय द्वारा 20 जुलाई, 2006 को पारित निर्णय और आदेश, जिसके द्वारा आदेश पारित किया गया - मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के तहत विद्वत विचारण न्यायालय(इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) को संशोधित किया गया है। विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित अवार्ड की शर्तें और

विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा अब इसमें संशोधन करना होगा ध्यान दियाः

2. अपीलार्थियों और प्रतिवादी के बीच एक अनुबंध हुआ था कुछ कार्यों के निष्पादन के लिए अनुबंध में टिहरी जल बांध परियोजना। के बीच समझौता दलों को 29 मार्च, 1978 को निष्पादित किया गया था और कार्यों में प्रश्न 31 दिसंबर, 1985 को पूरे किए गए थे।. सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया था अपीलार्थी का-निगम 27 अप्रैल, 1986 को। फाइनल के रूप में प्रतिवादी का बिल-ठेकेदार तैयार नहीं किया गया था और बैंक गारंटी के माध्यम से प्रस्तुत प्रतिभूति राशि नहीं थी जारी किया गया, पक्षकारों के अनुसार मध्यस्थता के लिए चला गया अनुबंध/समझौते के तहत मध्यस्थता खंड। पाठ्यक्रम में अपीलार्थी की कार्यवाही करने वाले उपरोक्त मध्यस्थता का निगम ने एक अंतिम विधेयक प्रस्तुत किया जिसके अनुसार

प्रत्यर्थी-ठेकेदार इसे राशि प्राप्त करने का हकदार है Rs.10,17,461.09 के योग के अलावा किए गए कार्य के कारण रु. 12..50 जो निगम के पास जमा में पड़ा हुआ था। देय राशि के रूप में। प्रत्यर्थी-ठेकेदार के अनुसार, क्रिस्टलीकृत हो गया था, एक और मध्यस्थता कार्यवाही के मध्यस्थता खंड के अनुसार शुरू किया गयासमझौता।

3. उपरोक्त मध्यस्थता कार्यवाही में अधिनिर्णय था 29 जनवरी, 1996 को पारित किया गया

जिसमें प्रतिवादी को अभिनिर्धारित किया गया - ठेकेदार रुपये की राशि का हकदार होगा। 10,17,461 / - के साथ आह्वान की तारीख से 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज पुरस्कार की तारीख तक और 12 प्रतिशत की दर से दावे का पुरस्कार की तारीख से भुगतान तक या प्रति वर्ष

पुरस्कार को न्यायालय का नियम बनाया जाता है, जो भी पहले हो। जहाँ तक प्रत्यर्थी का दावा-रुपये की राशि के लिए ठेकेदार। 12.50 निगम के पास जमा में पड़े लाखों, मध्यस्थों ने पकड़ा कथित राशि विवाद के दायरे से बाहर होनी चाहिए मध्यस्थता कार्यवाही में। तदनुसार, प्रतिवादी ठेकेदार के पास उक्त दावे को निपटाने का विकल्प छोड़ दिया गया था सौहार्दपूर्ण तरीके से या वसूली के लिए दीवानी मुकदमे का सहारा लेक उसी से।

4. अवार्ड के विशिष्ट भागों के खिलाफ आपत्तियाँ जिसे संबंधित पक्षों ने व्यथित महसूस किया था, 821 के समक्ष दायर किया गया था ,विद्वान जिला न्यायाधीश, टिहरी, गढ़वाल ने 15 अक्टूबर, 1997 के अपने आदेश द्वारा दावे को बरकरार रखा। प्रत्यर्थी-ठेकेदार की कुल राशि Rs.10,17,461 / अवार्ड के रूप में लाखों। जहाँ तक रुपये का दावा है। 12.50 लाख है संबंधित, विद्वत विचारण न्यायालय, इस तथ्य के बावजूद कि मध्यस्थ ने उक्त दावे का फैसला नहीं किया, मुद्दे में गया और प्रत्यर्थी-ठेकेदार को उक्त का हकदार ठहराया राशि भी। इसके बाद, एक आदेश पारित किया गया था जिसके संबंध में उन दोनों राशियों पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज पेन्डेंट लाइट और पद पुरस्कार अवधि के लिए 6 प्रतिशत। से व्यथित विद्वान जिला न्यायाधीश, टिहरी द्वारा पारित उपरोक्त आदेशके विरुद्ध, अपीलार्थी ने उत्तरांचल के उच्च न्यायालय का रुख किया अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपील दायर करना। उच्च न्यायालय ने 20 जुलाई, 2006 के अपने आदेश द्वारा आंशिक रूप से अपील को स्वीकार कर लिया।

जबकि Rs.10 का दावा, 17,461/- के पक्ष में दिया गया प्रत्यर्थी-जहाँ तक दावा किया गया है, ठेकेदार को रखा गया था से रु. 12.50 लाख का सवाल है, उच्च न्यायालय ने लिया विचार कि उपरोक्त राशि विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णयित नहीं की जा सकती थी क्योंकि उक्त पात्रता द्वारा नहीं दी गई थी विद्वान मध्यस्थ। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने रिमांड लिया द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा निपटाया जाने वाला उपरोक्त दावा यह। जहाँ तक ब्याज के सवाल का सवाल है, उच्च न्यायालय ने मामले के उक्त पहलू पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया। व्यथित, निगम इस अदालत के समक्ष चुनौती दे रहा है उच्च न्यायालय द्वारा 20 जुलाई, 2006 को पारित निर्णय और आदेश

उत्तरांचल का न्यायालय।

5. हमने श्री पुनीत तनेजा को सुना है, जिनके लिए विद्वान वकील हैं अपीलार्थी और श्री एस. बी. उपाध्याय, विद्वान वरिष्ठ वकील उत्तरदाता के लिए।

6. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि अवैतनिक राशि के लिए प्रत्यर्थी-ठेकेदार के दावे अंतिम बिल के साथ-साथ प्रतिभूति जमा की वापसी/वापसी के लिए, बैंक गारंटी के माध्यम से प्रस्तुत राशि सहित, था पक्षकारों के बीच पूर्व मध्यस्थता का विषय। में। उक्त मध्यस्थता के दौरान अंतिम विधेयक को निगम के समक्ष रखा गया था। निगम द्वारा मध्यस्थ। उपरोक्त की जांच परअंतिम बिल प्रतिवादी-ठेकेदार ने दो विशिष्ट बिलों का दावा किया विचाराधीन राशि और एक अन्य प्रक्रिया का सहारा लिया प्रथम मध्यस्थता में अनुमति लिए बिना मध्यस्थता। मध्यस्थता के दूसरे दौर का सहारा लेने के लिए कार्यवाही। अतः निर्णय की ओर ले जाने वाली मध्यस्थता कार्यवाही इस प्रकार है -

बिना किसी कानून के अधिकार के। विशिष्ट सहयोगी, जहाँ तक राशि 12.50 लाख रु. से का संबंध है। अपीलार्थियों के वकील ने कहा कि उक्त राशि पर निर्णय नहीं लिया गया था

मध्यस्थों द्वारा और उसी द्वारा वसूल किया जाना था एक सौहार्दपूर्ण प्रक्रिया या एक दीवानी मुकदमे का सहारा लेकर। ऐसे में स्थिति यह स्पष्ट रूप से सीखा परीक्षण की शक्ति से परे था न्यायालय प्रतिवादी के पक्ष में उक्त दावे को मानेगा ठेकेदार। यद्यपि उच्च न्यायालय ने रुपये के उक्त दावे को खारिज कर दिया था। उपरोक्त कारण के लिए 12.50 लाख, यह द्वारा उक्त मुद्दे के निर्णय का निर्देश नहीं दिया जा सकता इसके द्वारा नामित मध्यस्थ जैसा कि आक्षेपित द्वारा किया गया है उच्च न्यायालय का आदेश। विद्वान वकील के अनुसार, प्रत्यर्थी के उक्त दावे का न्यायनिर्णयन-ठेकेदार, यदि बिल्कुल भी हो, तो एक प्रक्रिया द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए था जिस पर विचार किया गया हो। मध्यस्थता समझौते के विशिष्ट प्रावधानों द्वारा दलों को। जहाँ तक ब्याज अनुदान का संबंध है, सीखा गया अपीलार्थियों के वकील ने खंड 1.2.14 पर भरोसा किया है और 1.2.15 पक्षों के बीच अनुबंध समझौते के भाग II का यह तर्क देना कि समझौते के उपरोक्त खंडों के तहत दलों को शासित करने के लिए एक विशिष्ट प्रतिबंध था ब्याज। इस न्यायालय के कई निर्णयों पर निर्भर करते हुए, जिन पर आगे होने वाली चर्चाओं में ध्यान दिया जाएगा, सीखा जाएगा वकील ने तर्क दिया है कि पक्ष में ब्याज का पुरस्कार प्रत्यर्थी-ठेकेदार स्पष्ट रूप से शर्तों के विपरीत है पक्षों के बीच समझौता पूरी तरह से असमर्थनीय है और इसलिए इस अदालत द्वारा हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता है।

7. की ओर से अग्रिम प्रस्तुतियों का विरोध करना अपीलार्थी, प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील-ठेकेदार इसने तर्क दिया है कि अपीलकर्ताओं ने तेहरी हाइड्रो देव में सक्रिय रूप से भाग लिय मध्यस्थों के समक्ष कार्यवाही और इसलिए, इस स्तर पर, मध्यस्थों के अधिकार क्षेत्र पर सवाल नहीं उठा सकते हैं विचाराधीन पुरस्कार। यह दावा किया जाता है कि Rs.10 की राशि के लिए प्रतिवादी, 17,461/- आयोजित किया गया है हमेशा अपने पक्ष में, यह किसी भी आधार का खुलासा नहीं करता है हस्तक्षेप के लिए। अब तक की राशि में रु। 12.50 लाख है जिस तरह से नए सिरे से निर्णय की आवश्यकता होती है , निष्पादित किया। जहाँ तक ब्याज का सवाल है, विद्वान वकील ने अदालत के समक्ष यूपी सिविल कानूनों को रखा है (सुधार और संशोधन) अधिनियम, 1976 जिसके द्वारा कुछ उत्तर प्रदेश राज्य में अपने आवेदन में। अदालत का ध्यान पैराग्राफ 7 ए की ओर खींचा गया है जिसे बाद में जोड़ा गया है ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम अमृतसर गैस सेवा और अन्य 1, राज्य उड़ीसा बनाम बी. एन. अग्रवाल 2 और एशियन टेक लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य 3 2009 10 एस. सी. सी. 354 (पैरा 21)।

8. यू. पी. सिविल कानूनों का पैरा 7 ए (सुधार और ऊपर निर्दिष्ट संशोधन) अधिनियम, 1976 अब हो सकता है -

पुनरुत्पादितः

" 7 ए. कहाँ और जहाँ तक पुरस्कार भुगतान के लिएअंपायर के मध्यस्थ, पुरस्कार में, ऐसी दर पर ब्याज का आदेश दें जो मध्यस्थ या अंपायर दे सकते हैं। प्रदत्त मूल राशि पर भुगतान करना उचित समझते हुए, मध्यस्थता शुरू होने की तारीख से धारा 37 की उप-धारा (3) में परिभाषित, की तारीख तक पुरस्कार, इस पर दिए गए किसी भी ब्याज के अलावा

1. [(1991) 1 एससीसी 533।

2 . [(1997) 2 एससीसी 469।

3 . 2009 10 एस. सी. सी. 354 (पैरा 21)।

ऐसे प्रारंभ से पहले की किसी भी अवधि के लिए मूल राशि, छह प्रतिशत से अधिक की दर पर अतिरिक्त ब्याज के साथ प्रति वर्ष जैसा कि मध्यस्थ या अंपायर मान सकते हैं तारीख से ऐसी मूल राशि पर उचित भुगतान की तारीख तक या ऐसी पूर्व तिथि तक पुरस्कार मध्यस्थ या अंपायर उचित सोच सकते हैं, लेकिन किसी भी मामले में नहीं पुरस्कार पर पारित की जाने वाली डिक्री की तारीख से

आगे।

9. जहाँ तक निर्णय लेने के लिए मध्यस्थ की अधिकारिता का संबंध है Rs.10 के दो दावों पर, 17,461/- और रु। 12.50 लाख हैं संबंधित, विवाद कम समय में हल करने में सक्षम है कम्पास। प्रत्यर्थी की पात्रता-ठेकेदार को उपरोक्त दो राशियाँ पहले की विषय वस्तु नहीं थीं। मध्यस्थों के समक्ष कार्यवाही जो उत्पन्न हुई प्रत्यर्थी की शिकायत-ठेकेदार कि हालांकि कार्य का निष्पादन पूरा हो चुका था, अंतिम बिल नहीं था तैयार किया गया और आगे कहा गया कि प्रतिभूति के रूप में जमा की गई कुछ राशियों को वापस नहीं किया गया था। एक बार अंतिम बिल था मध्यस्थों के समक्ष दावा तैयार और रखा गया उत्तरदाता-ठेकेदार क्रिस्टलीकृत हो गया। ये हैं खास पास हो गया। अतः यह कहना सही नहीं होगा कि मध्यस्थता ठेकेदार के विशिष्ट दावों के संबंध में कार्यवाही पूर्ववर्ती मध्यस्थता कार्यवाही को देखते हुए वर्जित था दलों के बीच। इसके अलावा, द्वारा पारित एक आदेश 15 जनवरी, 1994 को मध्यस्थ, जो अभिलेख पर उपलब्ध है प्रत्यर्थी के जवाबी हलफनामे के लिए एक संलग्नक के रूप में, यह

ऐसा प्रतीत होता है कि 15 तारीख के उपरोक्त आदेश में मध्यस् जनवरी, 1994 ने स्पष्ट रूप से दर्ज किया था कि "। . . . दोनों पक्षों इस बात पर सहमत हैं कि हमें संबंधित दोनों विवादों पर निर्णय लेना चाहिए रुपये की जमा राशि की वापसी। 12. 50 लाख और अंतिम बिल का भुगतान रु. की धुन। 10.00 लाख और विषम। . . . " इन परिस्थितियों में, पुरस्कार के दावे के रूप में Rs.10,17,461/- विद्वान मध्यस्थ द्वारा बनाया गया और द्वारा पुष्टि की गई नीचे दिए गए विद्वान न्यायालयों को आगे की जांच की आवश्यकता हमे नही पड़ेगी 1

10. जहाँ तक रुपये की राशि के संबंध में दावा है। 12.50 लाख का संबंध है, यह पहले ही देखा जा चुका है कि प्रत्यर्थी का हक-उक्त राशि के लिए ठेकेदार जमीन पर मध्यस्थों द्वारा निर्णय नहीं लिया गया था कि उक्त मुद्दा एक मध्यस्थ मुद्दा नहीं था और इसे या तो एक सौहार्दपूर्ण प्रक्रिया द्वारा या इसके माध्यम से हल किया जाना चाहिए वसूली के लिए एक सूट। यदि उपरोक्त दावे पर निर्णय नहीं लिया गया था मध्यस्थों द्वारा विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा उक्त दावे का आदेश देने में स्पष्ट रूप से गलत था। इसलिए, उच्च न्यायालय ने डिक्री के उक्त हिस्से को उलटने में पूरी तरह से उचित था। हालाँकि, हमें लिए गए दृष्टिकोण के लिए कोई उचित आधार नहीं मिलता है उच्च न्यायालय द्वारा कि प्रत्यर्थी का हक उक्त राशि का ठेकेदार अब उसके द्वारा नामित मध्यस्थ द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। बल्कि, हमारे अनुसार, उपरोक्त मुद्दे को निर्धारण के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए

था पक्षों द्वारा सहमत प्रक्रिया के अनुसार, यदि पार्टियाँ, बिल्कुल भी, आगे के दौर में जाने के लिए इच्छुक हैं इस स्तर पर निर्णय। इसलिए हम इसमें हस्तक्षेप करते हैं उच्च न्यायालय के आदेश का उपरोक्त भाग और, हमारे अधीन ऊपर की टिप्पणियाँ, हम पक्षों को उनके काम करने के लिए छोड़ देते हैं उपचार जिन्हें सबसे अच्छा और सबसे उपयुक्त माना जा सकता है मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में।

11. यह अदालत को इस पर विचार करने के लिए प्रेरित करेगा कि क्या है में पक्षों के बीच विवाद की प्रमुख हड्डी ब्याज। खंड 1.2.14 और 1.2.15 जिन पर बहुत सारे तर्क हैं दोनों पक्षों के विद्वान वकील द्वारा आगे बढ़ाया गया हो सकता है अब नीचे निकाला जाएः

" भाग-11 अनुबंध की शर्तें

1. 2.14 विवादों इत्यादि के कारण विलंबित भुगतान के लिए कोई दावा नहीं। ठेकेदार इस बात से सहमत है कि नुकसान के ब्याज के लिए कोई दावा सरकार द्वारा विचार या देय नहीं होगा1 किसी भी धन या शेष राशि के संबंध में जिसके पास हो सकता है किसी भी विवाद, मतभेद के कारण सरकार या प्रभारी अभियंता की ओर से कोई देरी या चूक तत्काल या अंतिम भुगतान करने में या किसी अन्य मे जो भी हो उसका सम्मान करें।

1.2.15 पैसे के लिए ब्याज ठेकेदारः प्रभारी अभियंता की ओर से भुगतान करने में कोई चूक नहीं मापने पर या अन्यथा देय राशि अनुबंध को दूषित या अमान्य करें, और न ही ठेकेदार किसी भी गारंटी या भुगतान पर ब्याज का हकदार होगा। बकाया और न ही किसी शेष राशि पर जो अंतिम समय पर हो सकता है उसके खातों का निपटान उसका होना चाहिए। ”

12. अनुबंध के उपरोक्त दो खंडों का पठन पक्षों के बीच समझौते से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इसके बावजूद द्वारा विचार की गई परिस्थितियों का कुछ अतिव्यापी दो खंड, विलंब के लिए ठेकेदार को कोई ब्याज देय नहीं है किए गए कार्यों के लिए या किसी भी कार्य के लिए अंतरिम या अंतिम भुगतान में गारंटी के रूप में जमा की गई राशि। उपरोक्त विचारित परिणाम दोनों पर लागू होगा ऐसी स्थिति जहाँ भुगतान को रोकना कुछ कारणों से है पक्षों के बीच विवाद या अंतर या अन्यथा भी।

13. द्वारा निर्दिष्ट इस न्यायालय के कई निर्णयों में से अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील के निर्णय में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने सचिव ,सिचाई विभाग, उड़ीसा सरकार और अन्य बनाम।

जी. सी. रॉय और अन्य । और कार्यकारी अभियंता, ढेंकलाल लघु सिंचाई डिवीजन, उड़ीसा और अन्य बनाम एन. सी. बुधराज (मृतक) द्वारा आइआरएस। और दूसरों को विशिष्ट सूचना की आवश्यकता होगी। सही अनुपात निर्धारित किया गया 4. (1992) 1 एससीसी 508। 5. (2001) 2 उपरोक्त में दो निर्णयों को विस्तृत रूप से दिया गया है। इसका मतलब है कि यदि पार्टियों के बीच समझौता नहीं होता है ब्याज के अनुदान और ब्याज के लिए एक पक्ष के दावे को प्रतिबंधित करना है मध्यस्थ को संदर्भित, मध्यस्थ के पास शक्ति होगी ब्याज देने के लिए। यह इस आधार पर है कि ऐसे मामले में मौन का (जहां समझौता मौन है) यह माना जाना चाहिए वह ब्याज समझौते का एक निहित शब्द था और, इसलिए, क्या ऐसा दावा मान्य है, इसकी जांच की जा सकती है - मध्यस्थ को दिए गए संदर्भ में। उपरोक्त दृष्टिकोण, विशेष रूप से, पेंडेंट लाइट ब्याज के संबंध में है। में एन. सी. में संविधान पीठ के बाद के निर्णय बुधराज के मामले (ऊपर) में भी ऐसा ही दृष्टिकोण अपनाया गया है। पूर्व संदर्भ अवधि के लिए ब्याज के संबंध में।

14. क्राफ्टर्स इंजीनियर्स के मामले में (ऊपर) कुछ हद तक पोर्ट ऑफ कलकत्ता बनाम के लिए न्यासी मंडल में इस न्यायालय के फैसलों से असंगत टिप्पणी आई। इंजीनियर-डी-स्पेस आयु 1 और मदनानी कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य पर भी ध्यान दिया गया। इसके बाद यह भी देखा गया कि इंजीनियर्स में निर्णय डी-स्पेस-एज के मामले (ऊपर) पर सईद में विचार किया गया था। अहमद एंड कंपनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, और मदनी निर्माण मामले (ऊपर) में निर्णय था श्री कामची अम्मान कंस्ट्रक्शंस बनाम. मंडल, रेलवे प्रबंधक (कार्य), पालघाट और अन्य।सईद अहमद के मामले (ऊपर) (पैरा 24) में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जी. सी. रॉय की संविधान पीठ के फैसले का प्रकाश

6. (1992) 1 एससीसी 508।

7. (1996) 1 एससीसी 516।

8 . (2010) 1 एससीसी 549।

9. (2009) 12 एससीसी 26.

10. (2010) 8 एससीसी 7 , मामला और एन. सी. बुधराज का मामला यह संदिग्ध है कि क्या इंजीनियर्स-डी-स्पेस-एज के मामले (ऊपर) में टिप्पणियाँ अनुबंध में एक्सप्रेस बार की अनदेखी करना, अच्छा कानून है। श्री मेंकामची अम्मान कंस्ट्रक्शंस का मामला (सुप्रा) जबकि मदनानी के मामले (ऊपर)

पर विचार करते हुए इस अदालत ने नोट किया कि मदनानी के मामले में निर्णय इंजीनियर्स में निर्णय का अनुसरण करता है डी-स्पेस-आयु का मामला (ऊपर)।

15. उपरोक्त चर्चाओं से यह स्पष्ट है कि जहाँ तक लटकते ब्याज का संबंध है, टिप्पणियाँ जी. सी. रॉय के मामले में फैसले के पैरा 43 और 44 में निहित (सुप्रा) मैदान को पकड़ेगा। यद्यपि उक्त सिद्धांत का सार पहले देखा गया है कि यह अभी भी बाहर निकलने के लिए उचित होगा जी. सी. रॉय के मामले (उपर्युक्त) में निर्णय का पैरा 44 जिसमें निम्नलिखित शर्तें हैंः

पैरा 44. उपरोक्त विचार को ध्यान में रखते हुए, हम सोचिए कि निम्नलिखित सही सिद्धांत है जो होना चाहिए इस संबंध में पालन किया जाए जहाँ पक्षों के बीच समझौता नहीं होता है ब्याज के अनुदान को प्रतिबंधित करें और जहां कोई पक्ष ब्याज का दावा करता हैऔर वह विवाद (मूल राशि के दावे के साथ या स्वतंत्र रूप से) मध्यस्थ को भेजा जाता है, वह होगा ब्याज लटकता अभिजात वर्ग को पुरस्कार देने की शक्ति। इसके लिए यह कारण यह है कि ऐसे मामले में यह माना जाना चाहिए ब्याज के बीच समझौते का एक निहित शब्द था पार्टियाँ और इसलिए जब पार्टियाँ सभी का उल्लेख करती हैं विवाद-या विवाद को ब्याज के रूप में संदर्भित करें मध्यस्थ के पास ब्याज देने की शक्ति होगी। इसका मतलब यह नहीं है कि हर मामले में मध्यस्थ को अनिवार्य रूप से ब्याज लंबित अभिजात वर्ग को देना चाहिए। यह एक बात है अपने विवेकाधिकार के भीतर सभी के प्रकाश में प्रयोग किया जाना मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्याय को ध्यान में रखते हुए "।

16. यूपी सिविल (सुधार और तहरी हाइड्रो देव) के प्रावधान। मध्यस्थता की पहली अनुसूची में संशोधन करने वालाअधिनियम, 1940 किसी भी मामले में प्रत्यर्थी ठेकेदार की सहायता नहीं करता है। ब्याज के पुरस्कार के दावे को बनाए रखने का तरीका, चूंकि, पहली अनुसूची के अनुच्छेद 7 क के रूप में, जैसा कि संशोधित किया गया है, एक ऐसी स्थिति जहाँ मनोरंजन के लिए एक एक्सप्रेस बार है या विलंबित भुगतान पर ब्याज का भुगतान किए गए कार्य या जमा में पड़ी राशि के लिए देय राशि सुरक्षा के रूप में। बी. एन. अग्रवाल के मामले में निर्णय (ऊपर) जिसके लिए विद्वान वकील द्वारा निर्भरता रखी गई है प्रतिवादी, एक बार फिर, के दावे का समर्थन नहीं करता है बी. एन. की तरह ब्याज के लिए उत्तरदाता अग्रवाल का मामला (ऊपर) संविधान पीठ के विचार जी. सी. रॉय के मामले में (ऊपर दिए गए) ब्याज के संबंध में लटकन नहीं हो सकता था और वास्तव में, दूर से भी नहीं थे। संदेह हुआ। बी. एन. अग्रवाल के मामले में पीठ की टिप्पणी कि G.C.Roy के मामले में (ऊपर) कार्यपालिका में निर्णय

एनिंजर (सिंचाई), बालीमेला और अन्य बनाम अभादुता जेना और अन्य 1 1 को खारिज नहीं किया गया था केवल के संदर्भ में था पूर्व संदर्भ अवधि के लिए ब्याज का पुरस्कार जारी करना। . प्रत्यर्थी द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए इंजीनियर्स-डी स्पेस-एज केस (ऊपर) में निर्णय पर ध्यान दिया जाता है धारा 11 में निहित ब्याज के भुगतान पर निषेध पक्षों के बीच समझौता विभाग और पहले से ही देखा गया है कि प्रस्तावों की शुद्धता इंजीनियर्स-डी-स्पेस-एज केस (ऊपर) में निर्धारित किया गया है इस न्यायालय के बाद के फैसलों में संदेह, संदर्भ जो पहले ही किया जा चुका है।

17. खंड 1.2.14 और 1.2.15, जो पहले से ही निकाले गए और विश्लेषण किए गए हैं, ने मनोरंजन या मनोरंजन पर एक स्पष्ट प्रतिबंध लगा दिया है। भुगतान न करने या देरी की किसी भी स्थिति में ब्याज का भुगतान किए गए या पड़े हुए कार्य के लिए देय राशि का भुगतान 11. (1988) 1 एस. सी. सी. 418। प्रतिभूति जमा। चर्चाओं के आधार पर इससे पहले हम यह विचार रखते हैं कि अनुदान Rs.10,17,461/- के दावे पर लटकता ब्याज नहीं है। न्यायसंगत है। पुरस्कार के साथ-साथ नीचे दिए गए न्यायालयों के आदेशों को उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

18. तथापि, अवार्ड के बाद की अवधि के लिए ब्याज का अनुदान यह कुछ अलग पायदान पर खड़ा होगा। यही मुद्दा है इस न्यायालय द्वारा बी. एन. अग्रवाल मामले में विस्तार से विचार किया गया है। (ऊपर) की धारा 29 के प्रावधानों के आलोक में मध्यस्थता अधिनियम, 1940। अंततः इस न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि ऐसी स्थिति में जहां पुरस्कार देने वाले मध्यस्थ द्वारा पारित किया गया हो। अवार्ड की तारीख से भुगतान की तारीख तक ब्याज है न्यायालय द्वारा संशोधित नहीं किया गया ". प्रभाव ऐसा होगा जैसे न्यायालय स्वयं डिक्री की तारीख से ब्याज प्रदान किया था भुगतान की तिथि। "उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, ब्याज अनुदान Rs.10 की राशि पर, पुरस्कार की तारीख से 17,461/- तक डिक्री की तारीख या भुगतान की तारीख, जो भी पहले हो, बरकरार रखा जाता है। मामले के तथ्यों में हमारा विचार है की ब्याज की दर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष होनी चाहिए जैसा कि निर्धारित किया गया है पक्षकारों के बीच मध्यस्थता कार्यवाही।

19. पूर्वगामी चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए हम इसकी अनुमति देते हैं, अपील आंशिक रूप से स्वीकृत की गयी,और उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20 जुलाई, 2006,को उपरोक्त वर्णित तरीको से संशोधित करें।

बी.बी.बी अपील आंशिक रूप से स्वीकृत की गयी।